राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 5647/2024

सेठपुरी पुत्र श्री कालूपुरी, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी स्वामियों का बास, माणकलो, थाना कारवार, जिला जोधपुर, राजस्थान।

---याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य, पीपी के माध्यम से

---प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री अशोक उपाध्याय श्री श्याम पालीवाल के लिए।
प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री विक्रम सिंह राजपुरोहित, पीपी और साथ
सुश्री सोनू मनावत, पीपी।

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

23/08/2024

1. याचिकाकर्ता यहां विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश संख्या 04, जोधपुर मेट्रो द्वारा आपराधिक विविध मामले (स्वतः संज्ञान जमानत निरस्तीकरण) संख्या 1731/2024 में पारित दिनांक 02.08.2024 के आदेश को चुनौती दे

रहा है, जो एफआईआर संख्या 252/2023, पुलिस स्टेशन भगत की कोठी, जिला जोधपुर से उत्पन्न हुआ है, जिसमें आईपीसी की धारा 420, 406 और 120-बी के तहत कथित अपराधों के लिए उसकी जमानत रद्द कर दी गई थी और उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था।

2. याचिका से संबंधित तथ्य सर्वप्रथम। शिकायतकर्ता ने रिपोर्ट की कि 21.10.2023 को उसने याचिकाकर्ता/आरोपी के साथ एक ट्रक के लिए किराया समझौता किया था। हालांकि, आरोपी ने तय किराया नहीं दिया और मांगे जाने पर किराया देने से इनकार कर दिया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने अपना ट्रक वापस मांगा, लेकिन याचिकाकर्ता/आरोपी ने न तो ट्रक वापस किया और न ही कोई किराया दिया, कथित तौर पर ट्रक को जानबूझकर जब्त कर लिया। इस प्रकार एक एफआईआर दर्ज की गई।

2.1. इस एफआईआर के दर्ज होने के बाद, पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और याचिकाकर्ता/आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसे संबंधित अदालत में पेश किया गया। अदालत ने बाद में आरोपी को सेंट्रल जेल, जोधपुर भेज दिया।

2.2. इस बीच, पुलिस ने इस मामले में 29.07.2024 को विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया। विद्वान सत्र न्यायालय ने तब 30.07.2024 के आदेश के तहत जमानत मंजूर की और याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा कर दिया गया।

2.3. यह पता चला कि अंतराल के दौरान, याचिकाकर्ता ने इस अदालत के समक्ष जमानत याचिका भी दायर की थी। याचिकाकर्ता के परिवार के सदस्यों और याचिकाकर्ता के वकील के बीच संवाद की कमी के कारण, एक वास्तविक संवादहीनता थी और याचिकाकर्ता सत्र न्यायालय को सूचित नहीं कर सका कि उसने पहले ही उच्च न्यायालय के समक्ष जमानत याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था।

2.4. इस आधार पर, विद्वान सत्र न्यायालय ने दिनांक 02.08.2024 के आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता की जमानत को स्वतः वापस ले लिया, जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता ने इस तथ्य को छिपाया था कि उसने एस.बी. आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 8071/2024 दायर किया था, जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था।

3. सुनवाई।

4. सबसे पहले, मेरा विचार है कि विद्वान जमानत न्यायालय का यह मत सही था कि याचिकाकर्ता ने चालाकी से काम लिया था और इस तथ्य को छिपाया था कि उसकी जमानत याचिका को उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले ही खारिज कर दिया था।

5. जमानत एक विवेकाधीन और न्यायसंगत राहत है, यह अच्छी तरह से स्थापित है कि इस तरह की राहत की मांग करने वाले व्यक्ति को अदालत में साफ हाथों से जाना चाहिए।

6. हालाँकि, यह देखते हुए कि उच्च न्यायालय ने इस आधार पर जमानत याचिका खारिज कर दी थी कि जांच अभी भी लंबित है, लेकिन बाद में, आरोप पत्र उसी दिन विद्वान निचली अदालत के समक्ष दायर किया गया प्रतीत होता है, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील, जो शायद उच्च न्यायालय द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बारे में नहीं जानते थे, ने परिस्थितियों में बदलाव के कारण तुरंत अगले दिन एक नई जमानत याचिका दायर की।

7. कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जांच पहले ही पूरी हो चुकी थी और आरोप पत्र दायर किया जा चुका था, इसलिए याचिकाकर्ता से आगे हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं थी। जैसा कि पहले ही देखा गया है, जमानत इस आधार पर रद्द नहीं की गई थी, बल्कि आरोपित जमानत आदेश में पहले से बताए गए कारणों से रद्द की गई थी, जिससे मैं सहमत हूं।

8. प्रासंगिक रूप से, अभियोजन पक्ष के वकील का यह भी कर्तव्य था कि वे निर्देश मांगते और याचिकाकर्ता और उसके उच्च न्यायालय के वकील के बीच गलतफहमी की खाई को भरने के लिए इस अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बारे में जमानत अदालत को अवगत कराते। विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, इस याचिका का निपटारा इस स्वतंत्रता के साथ किया जाता है कि याचिकाकर्ता जमानत रद्द करने वाली अदालत के समक्ष नई जमानत याचिका दायर कर सकता है और इस पर दिनांक 02.08.2024 के पूर्व जमानत रद्द करने के आदेश या इस अदालत द्वारा जमानत याचिका को पहले खारिज करने से प्रभावित हुए बिना निर्णय लिया जाएगा।

9. इस बीच, याचिकाकर्ता की नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, उसकी नई जमानत याचिका दायर करने तक, दो सप्ताह की अवधि के लिए उसके खिलाफ कोई बलपूर्वक कदम नहीं उठाया जाएगा। विद्वान सत्र न्यायालय से अनुरोध है कि जमानत याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होने के बाद उसी तिथि को निपटाया जाए।

10. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, निपटाया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।